S. No.	Name	(As on 31.3.1991) (Rs./Lakhs) Assets	Liabilities (Excluding Share Capital)
1	2	3	4
6.	National Textile Corpn. (M.P.), Indore	27578.91	24221.94
7.	National Textile Corpn. (SM), Bombay	48102.43	43558.82

जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध

*432. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटूभाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में जापान की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) भारत ने उच्च स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान, जापान के साथ आर्थिक सहयोग की गति तेज करने के माध्यम से तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अन्योन्य-क्रियाओं के माध्यम से जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और घनिष्ठ बनाने के प्रयास किए हैं। विदेश मंत्री ने जनवरी, 1992 में जापान की यात्रा की थी और जापान के विदेश मंत्री के साथ उपयोगी और रचनात्मक बातचीत की थी। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री और जापान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह वर्ष भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना और स्थायी शांति तथा भाई-चारे से संबद्ध भारत — जापान सन्धि हस्ताक्षर होने की 40वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है।

(ख) जापान की सरकार ने कहा है कि उनकी यह इच्छा है भारत के साथ जापान के संबंधों को और घनिष्ठ तथा व्यापक बनाया जाए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारता की नीतियों की सराहना की है। जनवरी, 1992 में जापान का एक उच्च स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा गया था ताकि भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने और पारस्परिक समझबूझ को घनिष्ठ करने के अवसर बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सके।

*433. [*Transferred to the 31st March*, 1992]

Election Commission's recommendations on electoral reforms

*434. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has recommended to the Government that candidates found violating the model code of conduct and guilty of corrupt practices should be automatically disqualified for a period of six years from contesting elections;

(b) if so, the reaction of the Government in this regard;

(c) whether in view of numerous incidents of booth capturing, Government propose to examine the recommendations for implementation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Government is undertaking an indepth study of the entire gamut of electoral reforms and the proposals received from the Election Commission arc being considered as part of the study.

उत्तर प्रदेश में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*435. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आदिवासी और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के विकास की कुछ योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में पांच अनुसूचित जनजातियां हैं और उनके निवास के क्षेत्र हैं: अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और